DAILY NEWS BULLETIN

LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE Day

Tuesday **20260811**

.

Govt: 2012 Rules for clinics ensure quality healthcare

Ananthakrishnan G
New Delhi, August 10

THE UNION Health Ministry has defended the constitutional validity of the 2012 Central Rules which require clinical establishments to charge for their procedures and services "within the range of rates determined by the Central government from time to time, in consultation with state governments".

The ministry said 'The Clinical Establishments (Central Government) Rules, 2012' were framed to "achieve" the mandate of Article 47 of the Constitution, which deals with the Directive Principles of State Policy.

In a counter-affidavit filed in the Supreme Court on August 4 in response to a batch of petitions challenging Rule 9 (ii), the government said that it "has been enacted to ensure that prices of healthcare services are neither exorbitantly high that they remain out of reach of common man, nor so abysmally low that there is no incentive for the industry to improve and grow".

The government said "Article 47 of the Constitution mandates the State, as one of its duties, to improve public health" and The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 and the 2012 Rules "have been enacted with the bona fide objective of improving the quality, safety, transparency, accountability and accessibility of healthcare services across the country".

> ***"The legislative framework seeks to prescribe minimum standards of services while ensuring that patients are informed of the charges levied by clinical establishments"***

"The legislative framework seeks to prescribe minimum standards of facilities and services while ensuring that patients are informed of the charges levied by clinical establishments. The provisions of the Act and the Rules are intended to promote public interest and strengthen the healthcare delivery system in furtherance of the constitutional mandate under Article 47...The law relating to provision of health services will be incomplete without necessary provision relating to affordability of health services," the government said.

The affidavit pointed out that "one of the primary requirements for registration is to ensure that all clinical establishments meet certain standards" and "fixing standards envisages within its scope all elements that make up a clinical establishment, such as the equipment used, the quality of employees, the standard of service provided and an integral element as also a consequence of these standards is the price of services provided. Whenever the law intends to deal with fixing standards, law may also contemplate and provide for — either expressly or otherwise — to fix the relevant price range in respect of such standards". Drawing a comparison, the government said: "The regulation of capitation fees in the case of professional educational institutions is a clear example of fixing standards."

The Centre said that the challenge to Rule 9(ii) "as being in violation of Article 14, 19(1)(g) and 21 of the Constitution is ill-founded and baseless" and it "has been enacted in pursuance of the State's positive obligation under Article 47 to improve public health".

The government said that the impugned provision "does not purport to prescribe uniform prices, rather a range of prices" but "enables clinical establishments to adjust their charges based on factors such as infrastructure, quality of service and patient demographics".

Reminding that 'health' is a State subject, the Centre said the CE Rules "will be applicable only when the Act is adopted and made applicable in a particular State or Union Territory. As per the provisions of the Act, it is within the ambit of powers of the States and Union Territories to adopt the Act under Clause (I) of Article 252 of the Constitution and thereafter implement and monitor the Act, and the role of the Central Government is restricted to prescribing the guidelines, categorisation, standards etc to facilitate the implementation of the Act".

एच1एन1 के मामले पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना बढ़े, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित

अनूप कुमार सिंह • जागरण

नई दिल्ली : राजधानी में मानसून के दौरान एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब पांच गुना से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले वर्ष 229 मामले एच1एन1 के मामले सामने आए थे, जबकि इस वर्ष अब तक 1344 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार वर्षा, जलजमाव में नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच अस्पतालों में बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस संबंधी परेशानी वाले मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इस दौरान एच1एन1 को लेकर स्कूल एडवाइजरी जारी नहीं की है पर शिक्षा निदेशालय स्कूलों को फ्लू के लक्षण वाले बच्चों को ठीक होने तक घर पर रखने की सलाह दे चुका है।

सफदरजंग अस्पताल में जुलाई में एच1एन1 के 11 पुष्ट मामले सामने आए। अगस्त में भी नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी मामलों में वृद्धि हुई है। पीएसआरआइ में एच1एन1 के मरीजों में कई गुना वृद्धि की बात चिकित्सकों ने बताई है। मैक्स अस्पताल में भी इस तरह के मामले बढ़े हैं। अस्पताल के कंसल्टेंट मेडिसिन डा. प्रतीक कटियान ने बताया कि मानसून में वायरल संक्रमण बढ़ते हैं पर लगातार बुखार, बढ़ती खांसी या सांस लेने में परेशानी को सामान्य वायरल मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमारी से पीड़ित लोगों में समय पर चिकित्सकीय इलाज जरूरी है। मानसून में डेंगू और एच1एन1 दोनों के मामले सामने आते हैं। दोनों में बुखार, कमजोरी और शरीर में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए डेंगू को लेकर भ्रम में रहने की बजाय लगातार तेज बुखार या सांस संबंधी परेशानी होने पर खुद से दवा लेने के स्थान पर चिकित्सक की सलाह से जांच कराना जरूरी है।

- शिक्षा निदेशालय की स्कूलों को फ्लू के लक्षण वाले बच्चों को ठीक होने तक घर पर रखने की सलाह
- इस मानसून में 1344 मामले, गत वर्ष इस दौरान थे 229, जुलाई में सफदरजंग में मिले 11 मामले

बच्चों-बुजुर्गों में गंभीर संक्रमण का खतरा : चिकित्सकों के अनुसार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग इन्फ्लुएंजा के लिहाज से अधिक संवेदनशील होते हैं। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द के साथ सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक सुस्ती या पानी-दूध पीने में दिक्कत हो तो तुरंत डाक्टर से मिलना चाहिए। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चार साल की बच्ची की एच1एन1 संक्रमण के बाद मृत्यु हुई। संक्रमण के कारण बच्ची में दिमाग की एक दुर्लभ जटिलता के संकेत मिले थे।

सरकारी अस्पतालों में बढ़ी निगरानी : आरएमएल, लोकनायक सहित दिल्ली के अन्य सरकारी अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में भी बुखार, खांसी और सांस संबंधी परेशानी वाले मरीज पहुंच रहे हैं। जीटीबी अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डा. प्रवीण ने बताया कि उनके यहां फिलहाल एच1एन1 के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। एनसीडीसी के दिशानिर्देशानुसार संदिग्ध मरीजों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।

पालतू पशुओं से घबराने की जरूरत नहीं : वर्ष 2009 की महामारी में कुछ कुत्तों और बिल्लियों में एच1एन1 संक्रमण पाया गया था। हालांकि वायरस का मुख्य प्रसार इंसान से इंसान में होता है। दिल्ली में पालतू पशुओं में बड़े पैमाने पर एच1एन1 संक्रमण की कोई रिपोर्ट नहीं है।

कैसे फैलता है एच1एन1 : एच1एन1 मच्छर से फैलने वाली बीमारी नहीं है। यह इन्फ्लुएंजा 'ए' वायरस से होने वाला सांस का संक्रमण है। यह वायरस पशुओं में भी पाया जाता है और समय-समय पर इसमें आनुवंशिक बदलाव हो सकते हैं। ऐसे बदलाव के बाद वायरस मनुष्यों को संक्रमित करने में सक्षम हो सकता है। एक बार मनुष्य में संक्रमण स्थापित होने के बाद यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।

बचाव की सलाह

- खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को रुमाल या मास्क से ढकें।
- हाथों को साबुन और पानी से बार-बार धोएं। हाथ धोए बिना आंख, नाक और मुंह को न छुएं।
- बुखार, खांसी या गले में खराश होने पर भीड़ और स्कूल से दूरी रखें।
- बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों में लक्षण दिखने पर डाक्टर से मिलें।
- तेज बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक सुस्ती, सीने में दर्द या होंठ नीले पड़ने जैसे लक्षण हों तो तुरंत अस्पताल जाएं।
- एंटीबायोटिक खुद से न लें। एच1एन1 वायरल संक्रमण है। डाक्टर के कहने पर एंटी वायरल दवा ले सकते हैं।
- फ्लू से बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा का टीका उपलब्ध है।

THE SPEAKING TREE

Yes, i'm Angry!

Anger, a universal emotion, is often negative and harmful. We need to learn how to look at anger, points out NARAYANI GANESH

Acknowledging and integrating the Shadow — our dark side that is home to negative emotions like anger and greed — is a significant part of the individuation process in Jungian psychology. This involves recognising and accepting the Shadow aspects of the self, resulting in a more complete and balanced self-awareness. It helps reduce the power of the Shadow to influence behaviour unconsciously and reduces the tendency to project the Shadow onto others. It also recognises the shared humanity in us all. In a broader cultural context, collective recognition and integration of the Shadow could potentially lead to increased understanding and tolerance, reducing societal division and conflict. Swiss psychiatrist and analytical psychologist Carl Jung says, "The best political, social and spiritual work we can do is to withdraw the projection of our shadow onto others."

When you feel angry, and you yell and throw things, you tend to blame somebody else or a specific situation or circumstance, a failure, and so on, for this anger that is now rising like volcanic lava, erupting from your core, making you spew fire and brimstone, scorching everything within sight. It is only when you acknowledge the fact that you are angry, that it is your reaction — to that person, situation, circumstance or failure that is making you a living volcano — that you can even hope to rein it all in and find ways to calm down, to overcome this destructive outburst, to reflect so that you can respond in a rational manner.

Kaaren Maezen Miller, a Zen priest, admits that she wasn't an angry person until she became a Zen Buddhist. "Sure, i yelled. I slammed things, i broke things. But i wouldn't have called myself angry. It was always another person making me angry. How was that my fault?" She further says, "The night i flung my wedding ring across the lawn during an otherwise piddling argument with my husband, the truth began to dawn: I was a really angry person. But there was hope because i was an angry person with a Zen practice."

With regular practice of zazen, just sitting, Miller says, she has learnt to slow down and acknowledge her negative emotion, resisting its pressure and not giving in to anger. Katherine Hepburn is believed to have said, "No one can make me feel humiliated without my permission." We could extend this thought to anger, and say, nothing or no one can make me angry without my permission. When you allow anger to enter your space and take over, things spiral out of control. The key to your space is with you, so why invite this destructive emotion into your sanctum sanctorum, your inner space, your very being?

ARUNDYUTI DAS BASU

Learn how to look at anger, J Krishnamurti would say. In his book, *Freedom from the Known* he says: "One of the most common expressions of violence is anger. When my wife or sister is attacked i say i am righteously angry; when my country is attacked, my ideas, my principles, my way of life, i am righteously angry. I am also angry when my habits are attacked or my petty opinions. When you tread on my toes or insult me i get angry or if you run away with my wife and i get jealous, that jealousy is called righteous because she is my 'property'. And all this anger is morally justified. But to kill for my country is also justified. So when we are talking about anger, which is a part of violence, do we look at anger in terms of righteous and unrighteous anger according to our own inclinations and environmental drive, or do we see only anger? Is there righteous anger, ever? Or is there only anger?"

Freedom from violence and anger means everything to Krishnamurti – even more important than sex, food, and position, because "This thing is corrupting me," he says. "It is destroying me and destroying the world, and i want to understand it, i want to be beyond it... I can do something only if i am beyond anger myself, beyond violence, beyond nationality."

When you sense that an emotional storm is brewing, just observe it, acknowledge it, and stay calm and collected. Meditate. Count. Do not allow that intruder to grab you. Whoever or whatever is making you angry, it is you who are angry, so you have the power to also not be angry. Become a witness, observe, acknowledge, move on with loving detachment. The moment you get attached, you become a victim; you will get vandalised. ■

The writer is author of 'Anger: Why We Get Angry and How We Should Respond to Provocation'

'MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS SEEN ACROSS AFFECTED SAMPLES'

Doctors' Safety Alert Led to Sun Pharma Eye Drop Recall

AIOS recommended members to avoid using quarantined batches until probe is completed

Vikas Dandekar

Mumbai: Sun Pharma's decision to recall 11 eyecare products in July came after an influential body of eye specialists issued a patient safety alert the previous month about bacterial contamination of certain batches of its Predmet eyedrop, documents suggest.

The All India Ophthalmological Society (AIOS), a body of nearly 27,000 eye specialists, on June 19 informed its members that multiple ophthalmic institutions found contaminations consistent with pseudomonas species in some batches of the prescription medicine.

SEVERE INFECTIONS

Sun Pharma later withdrew the medicine used for treating conditions such as eye redness and itching caused by allergies to severe infections. It ordered a wider recall on July 17, covering 11 other eyecare products including Depopred2ML, Brinolar, Brizotim, Lotepred and Nepalact as a precautionary step.

The company did not disclose any specific reason that prompted it to take the step, stating only that the decision was made as a matter of "abundant precaution". The AIOS note, which ET has seen, stressed that patient safety was paramount given the potential risk of serious ocular infection associated with contaminated ophthalmic preparations. "AIOS recommends a precautionary approach until further information becomes available," it said.

The AIOS recommended its members to avoid using the quarantined batches until investigations were completed. It also advised doctors for heightened vigilance for ocular infections, particularly keratitis (inflammation of the cornea), postoperative infections, endophthalmitis (internal infection of the eye), or unexplained ocular inflammation in patients who may have been exposed to the product. "Promptly investigate suspected cases with appropriate workup and institute treatment as clinically indicated," it added.

The adverse events committee of the AIOS said similar microbiological characteristics were observed across multiple affected samples. "These findings raise concern regarding a potential common-source contamination and warrant immediate precautionary measures while investigations continue," it said.

AIOS did not respond to ET's queries. The severity of infection by pseudomonas, a family of bacteria found widely in nature, can range from mild and self-limiting infections to causing serious ocular damage to patients, said experts.

An acclaimed ophthalmic surgeon, however, told ET that to date he has not found any cases of endophthalmitis caused by the use of this product. On August 1, in a letter seen by ET, Sun Pharma alerted medical experts that roughly 26 eyecare products sold in India were "not manufactured from the affected facility".

The company did not disclose the affected manufacturing site or share details of the issues that resulted in the withdrawals. The note added: "These products are manufactured either at qualified alternative Sun Pharma manufacturing sites or at external manufacturing facilities that operate independently of the site where the issue was identified."

'NOT AFFECTED LIST'

Among the products listed by Sun Pharma on the "not affected list" were Cequa, Careprost LS, Gatilox DM, Timolet OD, and Cafta. In response to ET's queries, Sun Pharma said in a statement: "We have initiated a proactive voluntary withdrawal of some ophthalmic products as a matter of abundant precaution. Product quality and patient safety are important to us, and remedial measures have been put in place."

An industry expert said if there is credible evidence that a manufacturing facility has been contaminated, the response should be clear, transparent and decisive.

According to data from market intelligence firm PharmaTrac, India's ophthalmic drugs market is worth ₹4,721 crore, growing at 6% annually. Some of the top players are Allergan, Micro, Ajanta, Entod, Intas and Alembic.

Targeted tech approach, smart poles expected to boost fight against air pollution

Sophiya Mathew
New Delhi, August 10

A FIRST-OF-ITS-KIND target-based model to select pollution-control technologies and digital smart poles — that display live data on pollutants and may have tools installed like mists to clean the air — are expected to boost Delhi's fight against air pollution.

Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa told *The Indian Express* that after the ongoing trials and technical assessment, the government is planning to introduce a target-based model to select pollution-control technologies — companies and innovators under the model will have to demonstrate efficiency before being considered for wider deployment. Under the Delhi government's Innovation Challenge, launched last October, 22 technologies are being tested, including 13 aimed at vehicular emissions — one of the biggest contributors to Delhi's air pollution — and nine at reducing ambient pollution.

The government will shortlist the firms and invite bids through a request for proposal (RFP), he said. The technologies will then be evaluated against specified pollution-reduction targets. For instance, a technology that can demonstrate a 30% reduction in pollution would be preferred over one offering a 20% reduction, provided the claims are scientifically established and the technology meets other requirements, the Minister said.

What are smart poles?

Besides the display boards installed outside the Capital's air-quality monitoring stations, pollution parameters can now be read on smart poles. Close to Rajghat Memorial, one of the seven spots where these poles have been installed in Central Delhi, the digital display shows PM2.5 and PM10 levels, updated every five minutes, along with the volume of air it claims to have cleaned.

On Monday evening, the display read: "Total Air Cleaned (cu ft) Last 24 hours: 4,04,697."

The move comes as the Delhi Environment and Forests Department has extended by about a month the deadline for IIT Delhi, the National Physical Laboratory (NPL) and the International Centre for Automotive Technology (ICAT) to complete the evaluation of technologies currently under trial. The assessment was earlier expected to be completed by May, with recommendations to the government by July. The final recommendations are now expected by September 10, *The Indian Express* has learnt.

A smart pole near Raj Ghat Memorial. EXPRESS

22 technologies being tested

Among the technologies being tested are vehicle-mounted air filters, particulate matter collectors, retrofit emission control devices (RECDs) for BS-IV vehicles, dust collectors and after-treatment systems for heavy-duty diesel vehicles.

Ambient pollution-control technologies include large-scale air purifiers, air-treatment towers, pole and road-divider dust collectors and particulate aggregation systems.

The trials are being conducted at locations including ISBT Kashmere Gate, the Red Fort area, primary health centres, fire stations and roads in Punjabi Bagh, Kirti Nagar and Rohini, said officials.

IIT Delhi, National Physical Laboratory and International Centre for Automotive Technology (ICAT), are undertaking independent monitoring, with the aim of assessing the actual pollution-reduction performance of the technologies.

Among the technologies already deployed are an EV-mounted anti-smog gun, the PAWAN III roadside pollution-control system and the ShuddhVayu vehicle-mounted air filter.

At Satguru Ram Singh Marg (Rama Road), 21 units of the STR-101 filter-free air-purification system have been installed on electricity poles along the central verge. Officials said the systems can treat nearly three lakh litres of air an hour and is being monitored through IoT-based systems.

The EV-mounted anti-smog gun, being tested along the Kirti Nagar-Mayapuri stretch, uses high-pressure water sprays to settle dust and other particulate matter, officials said. PAWAN III, installed near the Kirti Nagar Fire Station, draws polluted air from near the road and passes it through a multi-stage purification system.

Sirsa said these are pilot deployments, and technologies that perform well during the trials could subsequently be taken up on a larger scale.

2,500 homeless children mapped across city

Lavpreet Kaur
NEW DELHI

Delhi Police has mapped around 2,500 homeless children found begging in public places and at major road intersections to support the 'Child Beggar-Free Delhi' campaign announced by Chief Minister Rekha Gupta on August 8.

The survey was conducted by the Special Police Unit for Women and Children (SPUWAC) from July 1 to July 31 as part of 'Child Safety Month'.

Deputy Commissioner of Police (SPUWAC) Neha Yadav said the survey focused exclusively on children who were completely shelterless, with most of them found in west Delhi.

The children's latitude and longitude coordinates, and photographs will be shared with the Department of Women and Child Development and the Delhi Commission for Protection of Child Rights. The campaign will address their homelessness and vulnerability to crime, including being forced or drawn into activities such as snatching or working as couriers for drug peddlers.

HPV वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं

NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: लक्ष्मी योजना के लिए महिलाओ को खुद या अपनी बेटी को HPV वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नही है। आवेदन के दौरान इसे लेकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, ताकि लोगो को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा सके। अगर किसी महिला ने खुद या अपनी बेटी को HPV वैक्सीन नही लगवाई है, तो उसे दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए अपात्र नही माना जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि HPV वैक्सीन के अलावा पेड़ लगाना, सफाई करना और परिवार के सभी सदस्यो के आधार कार्ड बनवाना जैसी बाते भी इस सूची मे इसी तरह शामिल है।

इलाज की उम्मीद में रातभर अस्पताल के बाहर कतार

एम्स में एक किलोमीटर तक लगी मरीजों की लाइन, खुद संभालते रहे व्यवस्था, सफदरजंग में भी आधी रात से जुटे मरीज-तीमारदार

किसी की आंखों में दर्द था, किसी का दिल कमजोर। किसी के कंधे पर बीमार मां-बाप थे तो किसी की गोद में बच्चे, और सबकी आंखों में इलाज की उम्मीद। देश के नामचीन एम्स में इलाज की पहली सीढ़ी, ओपीडी की पर्ची तक पहुंचने के लिए उन्हें शाम आठ बजे से सुबह आठ बजे तक इंतजार करना पड़ा। रात गुजर गई, लेकिन कतार खत्म नहीं हुई। बारिश में लोगों ने बोतल, रुमाल और कागज से अपनी जगह बचाई। सफदरजंग में भी हालात अलग नहीं थे। मरीजों की पीड़ा समझने के लिए अमर उजाला [illegible] और संवाद न्यूज एजेंसी के सहयोगी [illegible] ने पूरी रात इनके बीच गुजारी। वह इसलिए भी कि देश के बड़े अस्पतालों की तरफ उम्मीद भरी नजर पूरे देश की रहती है...

ग्राउंड रिपोर्ट

दो बड़े संस्थान... हालात एक जैसे

[illegible]

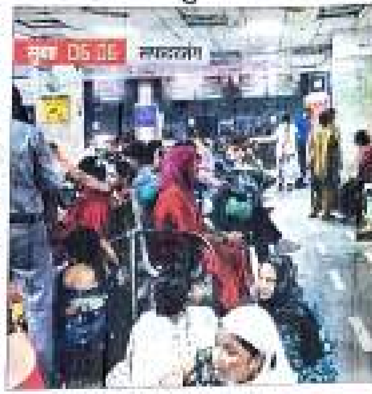

ओपीडी में मरीजों की भीड़। [illegible]

सफदरजंग में आधी रात से जुटने लगे मरीज, सुबह मिला इलाज का नंबर

[illegible]

ट्रॉमा सेंटर के हालात खराब, वेटिंग हॉल में एसी बेअसर, टूटी बेंचों पर इंतजार

[illegible]

बारिश आई तो कतार में चप्पल-बोतल और अखबार बना लोगों की पहचान

[illegible]

अस्पताल की दूसरी व्यवस्थाएं भी खुद संभालने की चुनौती दिखाई दी

[illegible]

पहला बैरियर चार बजे टूटा, अगले चार घंटे में चार पड़ाव पार

[illegible]

गेट नंबर एक के बाहर दिल के मरीजों की लगी कतार

[illegible]

एम्स : एक नजर

[illegible]

एम्स में ओपीडी के लिए ऐसे करवाएं पंजीकरण

[illegible]

शकरपुर में आवारा पशुओं से लोग परेशान

[illegible]

शास्त्री पार्क मेन रोड पर पड़ा कूड़े का ढेर

[illegible]

सुमित कुमार

गंदे पानी और दुर्गंध से मिलेगी राहत

[illegible]

भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा

1800-121-1166

अमर उजाला दिल्ली युवा Youth

मानसिक स्वास्थ्य और कॅरियर में मदद करेगा छात्र सुविधा केंद्र

डीटीयू में होगा निर्माण, यूजीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र स्थापित करने की अधिसूचना जारी

ललित कौशिक

नई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में छात्रों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को लेकर स्टूडेंट सर्विस सेंटर (छात्र सुविधा केंद्र) स्थापित किया जाएगा।

छात्रों को एक छत के नीचे काउंसलिंग से लेकर छात्र कल्याण से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें केंद्र की स्थापना और संचालन को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के छात्र स्वास्थ्य, खेल एवं मानसिक कल्याण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेगा। केंद्र छात्रों के लिए सिंगल-विंडो प्रणाली के रूप में काम करेगा, जहां मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक सहयोग, शारीरिक फिटनेस, खेल गतिविधियों और छात्र सहायता से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

इसके साथ ही स्नातक पाठ्यक्रम में मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग और फिजिकल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जैसे क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने की भी योजना है।

केंद्र के संचालन की समय-समय पर समीक्षा के लिए एक स्थायी समिति गठित की जाएगी। साथ ही इसके लिए अलग बजट प्रावधान और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग और समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से सेवाओं को और मजबूत बनाया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण काउंसिलिंग करना केंद्र का उद्देश्य

केंद्र का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण काउंसिलिंग उपलब्ध कराना, तनाव, अवसाद, करियर संबंधी चिंताओं और अन्य मानसिक चुनौतियों से निपटने में सहायता देना, सकारात्मक और समावेशी परिसर संस्कृति को बढ़ावा देना है। केंद्र में पेशेवर काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा 24×7 ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, टेली-हेल्पलाइन, वीडियो काउंसिलिंग, समूह परामर्श, कार्यशालाएं और पीयर सपोर्ट कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। गंभीर मामलों को दिल्ली-एनसीआर के विशेषज्ञ चिकित्सकों और अस्पतालों में रेफर की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार खेल और शारीरिक फिटनेस को भी विशेष महत्व दिया गया है। योग, ध्यान, एनसीसी, एनएसएस, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं और अंतर-विश्वविद्यालय खेलों में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। विश्वविद्यालय नए छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता ओरिएंटेशन आयोजित करेगा।

के दिन आया स्वर्ण पदक अपने गुरु को समर्पित

साथ अपने खेलों में तीन पदक जीतने का वादा किया। पीएम बोले, मैं पिछले 12-13 सालों से इस

के आपके प्रयासों और नई ऊंचाइयों को छूने की

इंसान के व्यवहार को समझने के लिए चीन ने बनाया धरती जैसा एआई समाज

आभासी तंत्र में इंसानों जैसी इच्छाओं व व्यवहार वाले एक अरब एआई एजेंटों को लगाया

बीजिंग। चीन के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एआई आधारित आभासी तंत्र (सिमुलेशन सिस्टम) विकसित किया है, जो व्यापक स्तर पर इंसानी समाज व उसके व्यवहार को समझने के लिए अध्ययन कर रहा है। इसमें एक अरब से ज्यादा वर्चुअल इंसानी एजेंटों को लगाया गया है, जो वास्तविक इंसान के व्यवहार के विविध रूपों को समझने की कोशिश करेंगे।

इन एआई एजेंट्स को केवल सामान्य कंप्यूटर बॉट की तरह नहीं बनाया गया है, बल्कि इनमें व्यक्तित्व, स्मृति, विश्वास और इंसानों जैसी इच्छाओं व सामाजिक व्यवहार को दर्शाने की क्षमता शामिल है। शोधकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट को "लाइट सोसाइटी" नाम दिया है। इससे जुड़ा शोधपत्र "मॉडलिंग अर्थ स्केल ह्यूमन-लाइक सोसाइटीज विथ वन बिलियन एजेंट्स" शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मशीन लर्निंग (आईसीएमएल) में प्रस्तुत किया गया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इन प्रयोगों में सिस्टम ने वास्तविक सामाजिक घटनाओं और मानव व्यवहार की विविधता को काफी हद तक समझने की क्षमता दिखाई। एजेंसी

बड़े भाषाई तंत्र के साथ छोटे और ज्यादा तेज एआई मॉडल्स का इस्तेमाल

अब तक इस्तेमाल होने वाले एजेंट आधारित मॉडल में बड़ी संख्या में लोगों के व्यवहार को समझना करना मुश्किल था। इसकी एक वजह यह थी कि इन मॉडलों में लोगों के व्यवहार को अक्सर सीमित और पहले से तय नियमों के आधार पर दिखाया जाता था लेकिन लाइट सोसायटी में शोधकर्ताओं ने बड़े भाषाई तंत्र के साथ छोटे और ज्यादा तेज एआई मॉडल्स का इस्तेमाल किया है। इसे "मिक्सचर ऑफ मॉडल्स" तकनीक बताया गया है। इस तरीके से बड़ी संख्या में एआई एजेंट्स को एक साथ चलाना संभव हुआ और शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने एक अरब से ज्यादा स्वायत्त एजेंटों वाला आभासी समाज तैयार किया।

■ एआई एजेंटों को वास्तविक दुनिया का डाटा भी दिया गया

शोधकर्ताओं ने इन वर्चुअल एजेंट्स को वास्तविक दुनिया की जनसांख्यिकीय और सामाजिक जानकारी से जोड़ने के लिए वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे जैसे वास्तविक डाटा स्रोतों का इस्तेमाल किया। इसका उद्देश्य ऐसे एआई एजेंट तैयार करना था जो सभी एक जैसे व्यवहार न करें, बल्कि वास्तविक समाज की तरह अलग-अलग विचार, विश्वास और सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करें। यानी आभासी तंत्र में मौजूद हर व्यक्ति केवल एक बॉट नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार को सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग तरीके से मॉडल किया जा सकता है।

■ एआई की दुनिया में पैदा किए गए असल मानवीय हालात

शोधकर्ताओं ने इस सिस्टम को अलग-अलग सामाजिक प्रयोगों में इस्तेमाल किया। इनमें भरोसा और बड़े पैमाने पर किसी विचार या सूचना के समाज में फैलने जैसी परिस्थितियां शामिल थीं। इस दौरान यह देखने की कोशिश की गई कि अलग-अलग एआई एजेंट एक-दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, सूचना कैसे फैलती है और समय के साथ पूरा समाज किस तरह बदलता है। कोई खबर या अफवाह समाज में कितनी तेजी से फैल सकती है।

मेटा ने नया एआई मॉडल किया लॉन्च, जुकरबर्ग ने की ओपन-सोर्स की वकालत

वाशिंगटन। मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सोमवार को म्यूज स्पार्क नाम का नया ओपन-वेट एआई मॉडल पेश किया। उन्होंने चीनी प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबले लिए अमेरिका में ओपन-सोर्स एआई पर बाधाएं कम करने की मांग की। यह नया मॉडल अन्य प्रतिस्पर्धियों से छोटा है और एकल ग्राफिक्स कार्ड वाले मैक या पीसी पर आसानी से चल सकता है। द फ्यूचर इज फॉर एवरीवन शीर्षक वाले 14 पन्नों के निबंध में जुकरबर्ग ने एआई को कुछ ही हाथों में रखने के बजाय सबके लिए सुलभ बनाने का समर्थन किया। एजेंसी

लेजर से मच्छर खत्म कर रहा चीन

तकनीक

बीजिंग, एजेंसी। चीन की एक कंपनी मच्छरों के खात्मे के लिए एक अनोखी तकनीक विकसित की है। उन्होंने अपने नए 'एयर डिफेंस' डिवाइस का एक वीडियो जारी किया है, जो हाई-पावर्ड इंफ्रारेड लेजर का इस्तेमाल करके मच्छरों को चुटकियों में मार गिराता है।

वीडियो में इस डिवाइस को एक खुले फार्म (खेती वाली जगह) में काम करते देखा गया है। जब यह मशीन आसपास के इलाके में मौजूद मच्छरों पर तेज लेजर किरणें छोड़ती है तो पूरी जगह पर लेजर लाइटों का एक ऐसा जाल बन जाता है, जिससे पास का जंगल किसी 'डिस्को क्लब' जैसा दिखाई देने लगता है।

हवा में उड़ते मच्छरों की पहचान करती है मशीन

यह डिवाइस मच्छरों की पहचान करने और उनका पीछा करने के लिए लिडार तकनीक और सेंसर का इस्तेमाल करती है। जैसे ही यह मशीन हवा में उड़ते हुए मच्छर को डिटेक्ट (पहचान) करती है, तुरंत उस पर एक सटीक इंफ्रारेड लेजर बीम दागती है। यह लेजर किरण सीधे मच्छर के पंखों को निष्क्रिय कर देती है, जिससे मच्छर तुरंत नीचे गिरकर मर जाता है।

मच्छरों से फैलने वाले डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने और बिना किसी जहरीले केमिकल या कीटनाशक के कीटों पर नियंत्रण पाने के लिए इस तकनीक को बेहद कारगर और सुरक्षित माना जा रहा है। चीन के इस अनोखे 'लेजर डिफेंस सिस्टम' का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह तकनीक मच्छरों की पहचान कर उन्हें लेजर से निशाना बनाने पर आधारित है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस्तेमाल को लेकर परीक्षण किए जाने जरूरी हैं।

पेट का कैंसर लिवर तक पहुंचा, विशेष रणनीति से बचाई बुजुर्ग की जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: पेट का कैंसर लिवर तक फैल चुका था। 65 वर्षीय मरीज की हालत काफी गंभीर थी। बीमारी तेजी से फैल रही थी। इस कारण उनके जीवित रहने की संभावना कम ही थी, लेकिन सर गंगाराम अस्पताल के डाक्टरों के उपचार और मरीज की जिजीविषा ने बीमारी को जिंदगी पर भारी नहीं पड़ने दिया। डाक्टरों ने उपचार की रणनीति मरीज की बीमारी की स्थिति के अनुसार तय की। पहले दवाओं से कैंसर को नियंत्रित किया, फिर सर्जरी की गई।

बीमारी दो बार लौटी, दोनों बार स्थानीय उपचार से उसे नियंत्रित किया गया। प्रबंधन का कहना है कि वर्ष 2018 में उपचार शुरू होने के करीब आठ वर्ष बाद मरीज की बीमारी नियंत्रण में है और वह अपने सभी काम खुद कर पा रहे हैं।

डाक्टरों ने उपचार की शुरुआत कैपेसिटाबीन और आक्सालिप्लाटिन वाली कैपाक्स कीमोथेरेपी के साथ ट्रास्टुजुमैब नामक एचईआर-2 दवा से की। बीमारी पर लगातार नियंत्रण मिलने के बाद डाक्टरों की टीम ने कन्वर्जन सर्जरी के तहत पेट में मौजूद मुख्य ट्यूमर को निकाल दिया। जांच

सर गंगाराम अस्पताल में डाक्टरों ने पहले दवाओं से कैंसर को नियंत्रित का काम किया, इसके बाद की गई सर्जरी

में पाया गया कि इससे लिवर में मौजूद कैंसर पूरी तरह समाप्त हो गया है। उपचार के बाद मरीज की नियमित मानिटरिंग की गई।

वर्ष 2021 में सर्जरी वाली जगह के पास कैंसर के लक्षण दिखाई दिए। डाक्टरों ने इसका उपचार रेडियोथेरेपी से किया। सर गंगाराम अस्पताल मेडिकल आंकोलाजी के चेयरमैन डा. श्याम अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024 में लिवर में कैंसर का एक छोटा हिस्सा दोबारा सामने आया। इस बार डाक्टरों ने माइक्रोवेव एब्लेशन से कैंसरग्रस्त हिस्से को खत्म किया। इस दौरान एचईआर-2 उपचार भी जारी रखा। चिकित्सकों ने कैंसर के दोबारा सामने आने पर बीमारी के स्थान और स्थिति के अनुसार उपचार की रणनीति अपनाई। इससे बीमारी के नियंत्रण व मरीज के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने में मदद मिली।

Tapping defence human capital for education

The education sector presents an excellent opportunity for the Armed Forces to contribute skilled manpower to the Viksit Bharat initiative, which seeks to make India a repository of human capital by 2047. Apart from the National Education Policy (NEP 2020) initiative to hire professors of practice from among distinguished veterans of the armed forces with academic pedigree, there is little else that leverages the vast potential of thousands of retiring servicemen and women in the education sector. Given the current turbulence in the education space and the government's inclination towards further reform, this article suggests methodologies to leverage the multiple competencies of Armed Forces personnel in the education sector.

While attempts have been made by the services and the government to ensure that servicemen across ranks who retire every year are integrated into civil society and take up a second career, much can still be done to leverage the wide range of competencies that these disciplined citizens could offer the country in the process of nation-building. Leveraging the multiple competencies of men and women who have served the nation with selfless commitment in the education sector offers scope for immense value addition.

Arjun Subramaniam

The sheer diversity and range of competencies and educational qualifications possessed by retiring personnel must be carefully examined by the ministry of education and matched to suitable institutions and initiatives. As compared to earlier times, when most of the Personnel Below Officers Rank (PBORs) retired without a graduate degree, the situation has changed significantly today. Large numbers of PBORs, particularly from the navy and air force, acquire degrees during service through correspondence courses, while those from the Army Education Corps (AEC) may have had the opportunity to acquire graduate degrees while in service. These PBORs have excellent potential to teach in rural schools, especially in regions from where they hail.

Army PBORs from the Corps of Signals, Corps of Engineers and Corps of Electrical and Mechanical Engineers (EME), and technically proficient air force and naval PBORs, who have actively worked on ships, aircraft and systems, have excellent potential to teach in vocational training institutes and ITIs, in a regional language, Hindi, or English, depending on their abilities. As far as the navy and air force are concerned, a small percentage of PBORs even acquire a post-graduate degree and are capable of being trained and absorbed at the college level and, in a few cases, even at the university level. Of interest to the education sector should be those PBORs from all three services who have instructional experience at various training establishments with certification and potential to teach at vocational training institutes. The education ministry needs to curate customised teaching and instructional pedagogy courses for such personnel to familiarise them with existing teaching methodologies.

Most officers in the three services superannuate between the ages of 54-56. A growing number are seeking premature retirement (PR) between the ages of 40-50, and a few opt for PR even earlier due to compelling personal reasons. Many of these officers are post-graduates with varied competencies cutting across disciplines. Several of these officers have teaching and instructional experience in various institutions of professional learning, a comprehensive list of which can be obtained from the service HQs. While the corporate sector has welcomed retiring officers with open arms, the same cannot be said of the education sector, mainly because of poor pay scales and a lack of institutionalised government initiatives beyond the professor of practice initiative.

Several PBORs retire and settle down in their native villages/towns, taking up jobs in the unorganised sector or looking after their ancestral property. Those with graduate degrees can easily be motivated to become school teachers after specialised training that need not necessarily be a B.Ed. Some of the PBORs with a technical background can join vocational institutes, with more permutations and combinations existing if the right strategy is adopted. Moving up the value chain, officers with the requisite qualifications can easily join colleges, ITIs, and other vocational institutes as lecturers, administrators and counsellors after appropriate training. Highly qualified officers can be offered professorships depending on their experience, competence and willingness to integrate fully into the academic world.

There needs to be a ministry-to-ministry understanding and awareness drive, followed by familiarisation visits by the ministry of education and professionals from NCERT, UGC, and vocational institutes to various training establishments and units across the three services. These visits could be coordinated by the directorate of resettlement and would lay the foundation of a long-term relationship between the services and the education sector. The next step would be to identify vacancies and training requirements for integrating servicemen into the sector. Since higher education is being privatised in a big way, bringing the private sector on board is crucial for the success of this initiative. A sustained campaign that revolves around nation-building, influencing younger generations with discipline and commitment, and producing responsible citizens will go a long way in inspiring and motivating ex-servicemen to become teachers, instructors, and professors.

One of the major recommendations of the Sixth Pay Commission was to facilitate lateral transfer of ex-servicemen at all levels into the para-military services and central and state police forces. A similar move into the education sector is worth considering. Embracing such an initiative affords an excellent opportunity in nation building and inculcating the values of hard work, focus and discipline in the younger generation by veterans from the Armed Forces, at a time when the youth of the country are searching for meaningful direction.

Arjun Subramaniam is a retired air vice marshal and a visiting faculty at Kautilya School of Public Policy, Hyderabad.

The views expressed are personal